

(ख) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सूती धागे की मांग और उसका कुल उत्पादन कितना था तथा इसकी कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है, और

(ग) इस संबंध में अधिकारियों द्वारा झूठे प्रतिवेदन तथा झूठे आंकड़े दिये जाने के आरोप के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी):** (क) जी नहीं, सूती यार्न का निर्यात (जिसमें शत प्रतिशत निर्यातमुख एककों द्वारा किए जाने वाले निर्यात तथा अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत निर्यात शामिल नहीं हैं) वर्षानुवर्ष आधार पर घोषित की जाने वाली वार्षिक उच्चतम सीमा के भीतर नियमित होता है। सूती यार्न के निर्यात की उच्चतम सीमा की घोषणा अपरिष्कृत कपास का उत्पादन तथा घरेलू मांग, सूती यार्न का उत्पादन तथा कीमते, विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र के लिए यार्न की कीमतों आदि जैसे सभी सम्बद्ध कारकों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद की जाती है। वर्ष 1994 के लिए सरकार ने 100 मिलियन कि०ग्रा० की उच्चतम सीमा की घोषणा की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती यार्न के उत्पादन, स्पष्ट घरेलू खपत तथा कुल निर्यात के विवरण नीचे दिए गए हैं:—

(मात्रा मिलियन कि०ग्रा० में)

	1990-91	1991-92	1992-93
उत्पादन	1510	1450	1523
स्पष्ट खपत	1397	1326	1384
निर्यात	90	126	129

#### स्रोत-वस्त्र आयुक्त

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

#### Scarcity of Cotton Yarn

190. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that handloom weavers and power-looms in Tamil Nadu are starved of the vital raw material, the cotton yarn; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) While there is no problem in the availability of cotton yarn, the problem has been increase in the prices of cotton yarn.

(b) The increasing trend in the prices of yarn has been mainly due to increase in the raw-cotton prices. Government has taken note of the price situation and necessary corrective action has already been taken. These measures include suspension of export of raw-cotton, permission to import of raw-cotton and persuasion of the spinning industry in the private sector to bring down the yarn prices. As a result of Government's intervention, the Indian Cotton Mills' Federation has undertaken to supply hank yarn to handloom agencies at prices lower than that prevailing now.

#### Negative Subsidy on Cotton Production

191. SHRI BHUPINDER SINGH MAAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the cotton growers are subjected to negative subsidy to the tune of 206 per cent on their production, according to the details submitted by Government of India in GATT negotiations;

(b) if so, whether it is congenial to increase the production of cotton in India;

(c) if not, whether such inimical measures against the cotton growers are proposed to be withdrawn; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (d) The information is being collected.